जितना कठिन संघर्ष होगा जिंदगी उतनी ही शानदार होगी।
– अज्ञात

विचार-प्रवाह
देहरादून, शुक्रवार 29 नवंबर 2019
पेज थ्री
www.page3news.in

चीन की गांठ हॉन्ग कॉन्ग

इस तकनीकी पहलू को छोड़ दें तो भी इन चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि हॉन्ग कॉन्ग और चीन की सरकारों द्वारा कही जा रही यह बात गलत थी कि आम जनता में प्रदर्शनकारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।

राधा जोशी

हॉन्ग कॉन्ग में छह महीने से जारी अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां हुए स्थानीय चुनावों के नतीजे इन प्रदर्शनों के संदेश को और आगे ले जाने वाले साबित हुए हैं। रविवार को हुई 70 फीसदी से ज्यादा वोटिंग यह बताने के लिए काफी थी कि लोग इसे स्थानीय निकायों के एक सामान्य चुनाव के रूप में नहीं देख रहे थे। उन्होंने हालिया विरोध प्रदर्शनों और उनसे निपटने के शासन के तरीके को गंभीरता से लेते हुए इस पर अपनी सख्त टिप्पणी अपने वोटों के जरिए दी। नतीजा यह रहा कि कुल 18 में से 17 जिला परिषदों पर ऐसे उम्मीदवारों का कब्जा हो गया जो लोकतंत्र समर्थक माने जाते हैं और प्रदर्शनकारियों के पक्ष में हैं।

ये जिला परिषदें आम तौर पर बसों के रूट तय करने जैसे लोकल मसले ही देखती हैं, लेकिन पार्षदों की एक जिम्मेदारी ऐसी है जो इन चुनावों की प्रकृति को नितांत स्थानीय नहीं रहने देती। यही निर्वाचित पार्षद अपने बीच से 117 सदस्य चुनकर 1200 सदस्यों की उस समिति में भेजते हैं जिसका काम हॉन्ग कॉन्ग के चीफ एग्जीक्युटिव का चुनाव करना है। बाद में चीन सरकार इस पद पर उसकी नियुक्ति पर मोहर लगाती है। चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि इस बार इस रास्ते से उस समिति में पहुंचने वाले सभी 117 सदस्य लोकतंत्र समर्थक ही होंगे।

बहरहाल, इस तकनीकी पहलू को छोड़ दें तो भी इन चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि हॉन्ग कॉन्ग और चीन की सरकारों द्वारा कही जा रही यह बात गलत थी कि आम जनता में प्रदर्शनकारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। विरोध प्रदर्शनों को भले ही अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया भर के उदार लोकतांत्रिक मिजाज के लोगों का समर्थन प्राप्त रहा हो, लेकिन चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि यह मूलतरू हॉन्ग कॉन्ग की जमीन से उपजा वहां के लोगों का आंदोलन है, जो शासन की जिद के चलते बढ़ता चला गया। हालांकि आंदोलन का मुद्दा बने प्रत्यर्पण बिल के पीछे कैरी लैम की सरकार जो वजह बता रही है, उसे खारिज करना मुश्किल है। 2018 में हॉन्ग कॉन्ग की एक लड़की पुन ह्यू विंग की उसके बॉयफ्रेंड ने ताइवान यात्रा के दौरान हत्या कर दी और हॉन्ग कॉन्ग लौट आया।

मौजूदा कानूनों के मुताबिक चीन, ताइवान और मकाऊ में किए गए अपराधों के लिए किसी भी हॉन्ग कॉन्ग वासी को न तो हॉन्ग कॉन्ग में सजा दी जा सकती है, न ही उसे प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस स्थिति में बदलाव के लिए कैरी लैम ने वह बिल पास करवाने की कोशिश की जिस पर बवाल शुरू हो गया।

बहरहाल, इस पूरे प्रकरण का एक निष्कर्ष यह है कि 'विदेशी शक्तियों' का हौआ अब आंदोलनों से निपटने का बहुत अच्छा हथियार नहीं रह गया है, और दूसरा यह कि चीन और उसकी छत्रछाया में चलने वाली हॉन्ग कॉन्ग सरकार सख्ती दिखाकर इस आंदोलन से नहीं निपट पाएगी। उम्मीद करें कि दुनिया का नंबर 2 मुल्क चीन अपने ही एक अंग हॉन्ग कॉन्ग को लेकर हठधर्मिता से बचेगा।

अहंकार

धर्म-दर्शन

शिवदान। ध्यान विचार प्रक्रिया पर चर्चा और उसे एक केंद्र बिंदु तक लाने का काम करता है। कुछ लोग संपूर्ण विचार शून्यता की बात करते हैं। दूसरा रास्ता ब्रह्म के प्रकाश को देखने के लिए भौंहों के बीच ध्यान केंद्रित करने का है। मंत्रों का जप करना भी ध्यान का एक दूसरा तरीका है। अरुणाचल के रमन महर्षि का कहना है कि किसी इंसान को अपनी पहचान को खोजने के लिए ये सवाल पूछना चाहिए किरू 'मैं क्या हूं' ध्यान में व्यक्ति को ये सवाल करना चाहिए और फिर धीरे–धीरे विकास के क्रम में वो चौन और शांति को हासिल कर लेता है। ये सवाल सच में बेहद मायने रखता है कि अहंकार का स्रोत क्या है? इसका उत्तर हासिल करने के लिए आपको अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। इस भावना को छोड़ देना होगा कि आपका शरीर इस नाम, पेशे, क्षेत्र, भाषा और इस तरह की दूसरी पहचानों से जुड़ा है।

संपादकीय

जिद छोड़े अमेरिका

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। इसका नवीनतम परिणाम यह है कि ईरान ने बहुपक्षीय संधि के तहत यूरेनियम संवर्धन को लेकर खुद पर आयात सीमाएं तोड़ने का फैसला किया है। एटमी दायरे का विस्तार रोकने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों के लिए यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा झटका है। पिछले महीने अमेरिका ने ऐन वक्त पर ईरान के खिलाफ लड़ाई का फैसला टाल दिया था, जिससे लगा कि स्थितियां सुधार की दिशा में बढ़ेंगी। पर ऐसा नहीं हुआ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के लिए संवर्धित यूरेनियम की सीमा पार न करने की चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर अमेरिका उसके साथ बहुत बुरा कर सकता है। उनका यह बयान ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के इस वक्तव्य के बाद आया कि ईरान ने मई में घोषित अपनी योजना के आधार पर 300 किलोग्राम की सीमा पार कर ली है। हालांकि उन्ह्होंने यह भी कहा कि अपना यह कदम ईरान वापस भी ले सकता है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम की सीमा पार करने की पुष्टि की। इस मुद्दे पर ब्रिटेन ने भी अमेरिका का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान को ऐसे किसी कदम से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का बयान आया है कि ईरान को समझौते के तहत अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। अमेरिका जानता है कि ईरान से युद्ध उसके लिए भी घातक है लेकिन शायद ट्रंप ईरान को अपनी शर्तों पर बात करने के लिए मजबूर करना चाहते हों। हालांकि कई अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वाइट हाउस की रुचि बातचीत में नहीं दिख रही।

यह सही है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह की तत्परता राष्ट्रपति शासन लगाने और फिर हटाने की सिफारिश भेजने में दिखाई, उसे कोई अच्छा उदाहरण नहीं माना जाएगा।

महा-म्यूजिकल चेयर

लक्ष्मी प्रसाद

महाराष्ट्र में शुक्रवार की शाम और शनिवार की सुबह के बीच घटनाचक्र इतनी तेजी से घूमेगा, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा हो। देर शाम तक यह लगभग तय हो गया था कि राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तीनों पार्टियों में सत्ता में हिस्सेदारी के फॉर्म्युले पर भी आम राय बन गई थी। अचानक प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष और पार्टी विधायक दल के नेता अजीत पवार ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें पार्टी के सभी 54 विधायकों का समर्थन पत्र यह कहते हुए सौंपा कि वे बीजेपी के साथ हैं। अगली सुबह जब तक किसी को कुछ खबर होती, न केवल राज्य से राष्ट्रपति शासन उठा लिया गया बल्कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप–मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी दिला दी गई।

स्वाभाविक रूप से तमाम विपक्षी दल इस पर उद्वेलित हैं। वे न केवल केंद्र सरकार और राज्यपाल के आचरण पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि अजीत पवार के कृत्य को धोखाधड़ी भी करार दे रहे हैं। यह सही है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह की तत्परता राष्ट्रपति शासन लगाने और फिर हटाने की सिफारिश भेजने में दिखाई, उसे कोई अच्छा उदाहरण नहीं

माना जाएगा, लेकिन मामले का दूसरा पहलू यह है कि राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया है। आखिर फडणवीस विधानसभा चुनाव के बाद उभरी सबसे बड़ी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं।

संविधान के मुताबिक राज्यपाल जिसे भी उपयुक्त समझें सरकार गठन का मौका दे सकते हैं, सो उन्होंने मौका दिया है। हां, इसके बाद करने को उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता। बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि विधायकों के बहुमत का निर्णय सदन के पटल पर ही हो सकता है, कहीं और नहीं। अगले शनिवार प्रदेश राजनीति की दशा और दिशा भी वहीं से तय होगी। राजनीति में अजीत पवार का प्रताप–प्रभाव अब तक अपने चाचा शरद पवार की छाया के चलते ही था। पहली बार वे इस छाया से बाहर निकले हैं। देखना होगा कि पार्टी पर या विधायकों पर उनकी पकड़ वास्तव में कितनी है। विधानसभा में कितने विधायक वे अपने साथ ला पाते हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति के शिखर पुरुष शरद पवार को भी उम्र के इस पके मोड़ पर विकट राजनीतिक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। प्रदेश में एक अनूठा राजनीतिक प्रयोग उनके प्रयासों की बदौलत शुरू हो रहा था जो उनकी ही नाकामी के चलते बीच में अटक गया। शिवसेना और कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका नहीं रही। क्या वे पार्टी और प्रकारांतर से प्रदेश राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ का सबूत पेश करते हुए बीजेपी के इस चरखी दांव को नाकाम कर पाएंगे? आगे की राजनीति का स्वरूप काफी हद तक इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा, जिसके लिए हमें सदन में विश्वास प्रस्ताव के नतीजों का इंतजार करना होगा।

सूडोकु नवताल-5176

मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5175 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

Jagrutidaan.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

बैंक बना देने से नहीं बचेंगे पोस्ट ऑफिस

भरत झुनझुनवाला। भारतीय डाक विभाग के बढ़ते घाटे से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना की थी। विचार था कि दूर–दराज क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी की बदौलत पोस्ट ऑफिस इन क्षेत्रों तक बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करने का जरिया बन सकते हैं। लोगों को यह व्यवस्था पसंद आ गई तो इसके साथ ही पोस्ट ऑफिसों का धंधा भी चल निकलेगा। लेकिन मौजूदा हालात इस उम्मीद को खारिज करते हैं। पोस्ट पेमेंट्स बैंक के घाटे बढ़ रहे हैं। वास्तव में हमें डाक विभाग की मूल समस्या पर ध्यान देना चाहिए, जो यह है कि सूचनाओं के ऑनलाइन आवागमन से डाक की जरूरत बहुत कम हो गई है। हालांकि ऑनलाइन डिलिवरी ऑर्डरों को पहुंचाने के काम में भारी वृद्धि हुई है। इस खट्टे–मीठे परिवर्तन का तमाम देशों ने लाभ उठाया है। कनाडा में ऑनलाइन ऑर्डरों का दो तिहाई हिस्सा पोस्ट ऑफिसों द्वारा वितरित किया जाता है। वहां के डाक विभाग ने यह सुविधा दे रखी है कि खरीददार अपनी गाड़ी से आते–जाते डाक खिड़की से अपना पैकेट उठा सकता है।